

**F. No. IC-15/31/2026- Imp. Cell
Government of India
Ministry of Law and Justice
Department of Legal Affairs
(Implementation Cell)**

24108, Kartavya Bhawan-2, New Delhi
Dated: 22.07.2026

To,

The Secretary,
Bar Council of Delhi,
2/6, Siri Fort Institutional Area,
Khel Gaon Marg, New Delhi-49.

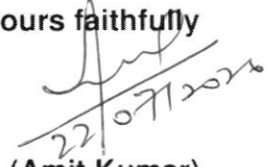
Subject: Improper use of the State Emblem of India by the Bar Associations of Delhi-reg.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of the complaint received from Shri Amarnath on the subject mentioned above and to say that the subject matter pertains to State Bar Council of Punjab & Haryana under Section 6(1) (dd) of the Advocates Act, 1961. Therefore, the same is being forwarded to the Bar Council of Delhi for taking necessary action on the matter as per the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 and State Emblem of India (Regulation of Use) Rules, 2007. Action taken in this regard may kindly be communicated to the to this Department.

2. This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully



(Amit Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India
Ph. No. 011-24016117 (O)
Email: impcell-dla@nic.in

D U

8/2026

सेवा में

1. गृह सचिव,
भारत सरकार
2. सचिव(उपभोक्ता मामले विभाग)
भारत सरकार
3. सचिव(विधि मामले विभाग)
भारत सरकार

COPY (C.A.)

सचिव(उपभोक्ता मामले विभाग)

भारत सरकार

सी.आर.ए.

भारत सरकार

E-379545/2026/14/1

विषय:- दिल्ली के वार एसोसिएशनों के द्वारा राष्ट्रीय संप्रतीक(National Emblem) के अनुचित प्रयोग के संबंध में।
महोदय/महोदया,

मैं आपका ध्यान दिल्ली एवं देश के अन्य राज्यों, के विद्वान अधिवक्ताओं/वकीलों/विधिक व्यवसायियों के एसोसिएशनों के द्वारा वाहन के पार्किंग लेवल पर भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक का अनुचित प्रयोग किया जाना प्रतीत हो रहा है। राज्यों एवं जिला के वार एसोसिएशन का राष्ट्रीय संप्रतीक का प्रयोग से सुरक्षा एवं ठगी का भारी खतरा हो सकता है, आम जनता यह समझती है कि राष्ट्रीय संप्रतीक का प्रयोग केवल सरकार के बड़े अधिकारी द्वारा ही किया जाता है, अतः एडवोकेट/वकील एक सरकार से संबंधित व्यक्ति है और कम-पढ़े लिखे सुरक्षा कर्मों जैसा होम गार्ड/दिल्ली सरकार के मार्शल/अर्द्ध सैनिक बल के जवान एवं पुलिस के जवान राष्ट्रीय संप्रतीक लगे वाहनों की चेकिंग में सख्ती से बचते हैं एवं नरमी बरतते हैं, धाराप्रवाह अंग्रेजी में कानूनी भाषा बोलने वाले विद्वान वकीलों से कौन धंका लें। यह तो कानून के विद्वानों के संगठनों द्वारा ही राष्ट्रीय संप्रतीक का ऐसा प्रयोग कानून के डार्क पैटर्न का सर्वोत्तम उदाहरण हो सकता है। यह अनुचित प्रयोग ना तो शासकीय और ना ही व्यवसायिक वक्तु राष्ट्रीय संप्रतीक के अनुचित प्रयोग महाठगी की श्रेणी में आता है।

2. मुझे अखण्ड विश्वास है कि दिल्ली के किसी भी वार एसोसिएशनों को सरकार के द्वारा राष्ट्रीय संप्रतीक के प्रयोग की कोई भी अनुमति नहीं मिली होगी। यहां तक की राष्ट्रीय संप्रतीक के उपर कुछ भी नहीं रखा या लिखा जाता है, लेकिन वार एसोसिएशन द्वारा अपना नाम लिखना राष्ट्रीय संप्रतीक का घोर राष्ट्रीय अपमान है। नीचे एडवोकेटों के एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का कुछ फोटो अटैच कर रहा हूँ। सरकार औपनीय तरीके से एक कमिटी बना कर वार एसोसिएशनों के सभी इकाई/न्यायालय के परिसर में खड़ी कारों में पार्किंग लेवल में अवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय संप्रतीक के प्रयोग की जाँच की जाए एवं विधि सम्मत मुकदमा/भारी जुर्माना एवं जुमनि का व्यापक प्रचार प्रसार भी की जाए ताकि अन्य लोग भी राष्ट्रीय संप्रतीक का अनुचित प्रयोग ना कर सकें। The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and Emblems and Name(Prevention of Improper use) Act, 1950 को ध्यान में रखते हुए मामलों की जाँच की जाए। इसे ऐसा ना समझा जाए कि यह तो केवल एक पार्किंग लेवल है, वक्तु यह देखा जाए की इससे आम जनमानस के भीतर क्या संदेश जाता है। विधि विद्वानों द्वारा यहाँ से राष्ट्रीय संप्रतीक के दुरुपयोग को उच्च कोटि का अपराध माना जाए और भारतीय न्याय संहिता की अन्य सुसंगत धारा के अन्तर्गत मामलों की जाँच की जाए।

3. अनुरोध है कि नाम एवं पहचान गुप्त रखी जाए अन्यथा ये वेलगाम वकील व्यवसायी कौम किसी को कहीं के भी कोर्ट में किसी भी बात पर घसीट लेंगे।

भवदीय

(अमरनाथ)



55

